

Yashoda Girls' Arts & Commerce College, Nagpur



Project in Environment Science

Session: 2021-2022

**Name of the Project: Impact of Environment on Social
Development**

Number of Students Enrolled: 09

Name of Co-ordinator : Dr. Lalita Punnaya




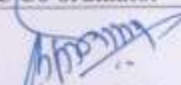
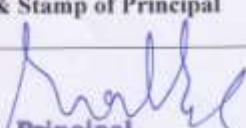
Yashoda Girls' Arts & Commerce College

Affiliated to Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University, Nagpur
NAAC Accreditation B++ with 2. 82 CGPA

Sneh Nagar, Wardha Road, Nagpur. 440015

Brief Report of Activity

Academic Year- 2021-2022

Name of Project	Project on Impact of Environment on Social Development	
Academic Year of the project	2021-2022	
Subject/ Course under which the project is taken	Environment Science	
Number of students Completing the course	09 Students	
Brief Report	The project on Impact of Environment on Social Development was given to the students of Environment Science as one of the compulsory course of RTM Nagpur University in which the project work is mandatory for the students to complete during the Session 2020-2021. Accordingly 09 students completed the project and submitted their project reports. They were awarded grades on their project work.	
Project outcomes	<ul style="list-style-type: none">• The students learnt a lot through the project regarding the impact of Environmental changes on social development.• They found out different aspects of the topic under study.• They completed the project under the guidance of the course co-ordinator.• They understood how the social development is affected by the increasing pollution and other factors damaging the environment.	
Number of Beneficiaries:	Students: 09	
Criterion No: I	Metric No: 1.3.2	
Signature of Course Co-ordinator	Signature and Stamp of IQAC Co-ordinator	Signature & Stamp of Principal
	 Co-ordinator, IQAC Yashoda Girls' Arts & Commerce College, Nagpur	 Principal Yashoda Girls Arts & Commerce College, Sneh Nagar, Nagpur-15



List of Students completing the Project



Purushottam Khaparde Health & Education Society's



Yashoda Girls' Arts & Commerce College, Nagpur

■ Recognized by Government of Maharashtra ■ Affiliated to RTM Nagpur University, Nagpur

SNEH NAGAR, WARDHA ROAD, NAGPUR - 440 015. (M.S.) INDIA

■ Tel. : 0712-2290637 ■ Fax No. : 0712- 2290368 ■ Website : www.yashodagirlscollege.edu.in ■ Email : ygc.ngp@rediffmail.com

YGC No./

Date _____

Project in Environment Science as per RTM Nagpur University Curriculum

Title of the Project on Impact of Environment on Social Development

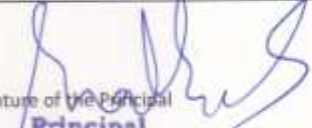
Number of students completing the project : 09

Session 2021-2022

Sr. No.	Name of the students enrollment in project
1	POOJA NARENDRA PRAJAPATI
2	ABOLI PRASHANT DHAMGAYE
3	ROSHNI SHAMRAO MASRAM
4	PRATIKSHA DINESH RAUT
5	DURGA HANUMAN DHAKATE
6	AISHARYS ANIL NEWARE
7	SAKSHI DEEPAK SHENDRE
8	MAYURI AJAY KATRE
9	SHIVANI DINESHPRASAD VISHWAKARMA



Signature of Project Co-ordinator

(Dr. Lalita Punnya)


Signature of the Principal

Principal
Yashoda Girls Arts & Commerce
College, Sneh Nagar, Nagpur-15




Co-ordinator, IQAC
Yashoda Girls' Arts &
Commerce College, Nagpur

Project Copy

2021-2022

INDEX

Name: Pooja N. Prajapati

Std: B. Com Div: II Roll No: _____

Sub: Environment (पर्यावरण) Project.

School / College: Yashoda Girls College.

Sr. No.	Date	Title	Remark	Pg. No.
		* सामाजिक छटक और विकास - विकास पर परियोजना करना सामाजिक छटक, करना, परियोजना		
		* प्रोजेक्ट तयार करने के प्रकार		
		1) परियोजना		
		2) प्रकल्प के महत्व और उद्देश्य		
		3) कार्यपद्धति		
		4) संकेतित क्षमताएं खोज		
		5) निष्कर्ष		
		6) उपाययोजना		

[Signature]



[Signature]

PRINCIPAL

Yashoda Girls Arts & Commerce College
Sheh Nagar, Nagpur-46

॥ भारतीय समाज ॥ का परिचय

(Introduction to Indian Society)

1) प्रस्तावना * → भारतीय समाज अत्यंत प्राचीन एवं संकीर्ण समाज रहा है। विभिन्न वंश के धर्म के भाषा के समूह एवं अन्य स्थलांतरित लोग भारतीय समाज में आते रहे हैं, तथा यहाँ के वातावरण में रच-बसगये प्रती नहीं, बल्कि अनेक कला एवं हस्त व्यवसायों का विकास भी हुआ था।

(क) भारतीय समाज का क्रमिक विकास :-

- 1) प्राचीन कालखंड
- 2) मध्ययुगीन कालखंड
- 3) ब्रिटिश कालखंड
- 4) स्वातंत्र्य कालखंड

प्राचीन कालखंड के भारतीय समाज का विकास जात करने के लिए निम्न बिंदुओं पर विचार करेंगे।

- (अ) सिंधु सभ्यता। (आ) आर्या का आगमन तथा आप्तिकरण की प्रक्रिया।
(इ) जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रभाव। (ई) हिन्दु समाज व्यवस्था।

भारतीय समाज की रचना और उसके विभागों का अध्ययन " सामाजिक संस्था " यह अवधारणा समाज-शास्त्र में केन्द्रमान पर है। " समाज-शास्त्र प्रायः सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करनेवाला विज्ञान है। " इसलिए किसी समाज का संकीर्ण एवं प्रथम स्वरूप समझने के लिए उस समाज की सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप का अध्ययन करना आवश्यक है।



(क) भारतीय समाज का क्रमिक विकास *

- 1) सद्गुणों का विकास
- 2) वास्तुविद्या का विकास
- 3) साहित्य का विकास
- 4) वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास
- 5) आर्थिक विकास का प्रोत्साहन

भारतीय जीवन के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, और विशेषतः धार्मिक पहलुओं पर धर्मों की गहन रचना अभिप्रेत छाप पड़ी है।

भारतीय समाज की रचना और उनके विभागों का अध्ययन किया है। " सामाजिक संस्था " यह अवधारणा समाजशास्त्र में केन्द्रस्थान पर है।

" समाजशास्त्र माने सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करनेवाला विज्ञान है। " इसलिए किसी समाज का संपूर्ण स्वरूप सशर्त स्वयं समझने के लिए उस समाज की सामाजिक संस्थाओं के स्वयं का अध्ययन करना आवश्यक है। यही तथ्य भारतीय समाज को भी लागू पड़ता है।

सामाजिक संस्था का अर्थ *

भारतीय समाज के विवाह, परिवार एवं जाति संस्थाओं का अध्ययन करने के पूर्व सामाजिक संस्था का अर्थ, व्याख्या एवं विशेषताओं का संक्षेप में विचार करेंगे। मानव प्राणियों का तथा मानव समाज का अस्तित्व और निरंतरता बनाए रखने के लिए उनके विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होना आवश्यक होता है। तथापि, कोई भी समाज अपने सदस्यों को अनिर्बंध तरीके से अपनी आवश्यकताएँ पूर्ण करने की स्वतंत्रता नहीं देता। विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार की जाए इस बारे में कुछ निम्नलिखित सामाजिक निर्धारित करता है।



इस नियमों एवं निर्बंधों को ही सामाजिक नियमन (नियंत्रण) कहते हैं। जब यह नियमन किसी एक आवश्यकता के साथ आवश्यक किए जाते हैं, तब उसे हम सामाजिक संस्था कहते हैं। इस प्रकार व्यक्तियों के एवं समाज के आवश्यकता पूर्ति के माध्यम (तरीके) अथवा पहली निश्चित करनेवाले सामाजिक नियमों के पूंज (Sum) को सामाजिक संस्था कहते हैं। विवाह, परिवार, राज्य, धर्म, मर्म, शिक्षा आदि सामाजिक संस्थाएँ हैं। सामाजिक संस्था का अर्थ अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए समाज-शास्त्रियों द्वारा बतलाई गई परिभाषाओं का विचार किया जा सकता है।

संस्था की परिभाषा *

- ① " सामाजिक संस्थाएँ सामान्य इच्छा द्वारा स्वीकृत और स्थापित मानवीय संबंधों की संगठित व्यवस्था हैं। "
- ② " सामाजिक संस्था सामाजिक विशेषताओं को स्पष्ट करनेवाले वह नियम हैं, जिनमें काफी स्थायित्व होता है। जिनका कार्य सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। "
- ③ " सामाजिक संस्थाएँ आचरण के वह नियम या प्रतिमान हैं जो मनुष्यों की प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित हुए हैं। "
- ④ " लोगों की आवश्यकताएँ उचित-सुप्रस्थापित कार्य पहली इन्व पूर्ण करने हेतु संगठित हुई मानव समाज की संरचना को ही संस्था कहते हैं। "
- ⑤ " समाज की एकाधिक मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति करने के लिए सामाजिक आंतरक्रियाओं को मार्गदर्शित करनेवाला - नियमों - प्रतिमानों का संच (Sum) ही सामाजिक संस्था कहलाता है। "



सामाजिक संस्था की विशेषताएँ *

- ① सार्वभौमिक / सार्वत्रिकता
- ② सामाजिक नियमों का पुंज
- ③ स्वतंत्र कार्यशैली
- ④ भौतिक साधन
- ⑤ चिन्ह या प्रतीक
- ⑥ आचार संहिता
- ⑦ पारस्परिक संबंध स्वयं निर्भरता
- ⑧ सापेक्षतः स्थिर या स्थायी

भारत में सामाजिक संस्थाएँ *

सामाजिक संस्था का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं का अध्ययन करने के बाद इसे भारत की विवाह, परिवार एवं जाति इन सामाजिक संस्थाओं के बदलते स्वरूप का अध्ययन करना है। तत्पूर्व इसे विवाह का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं का संक्षेप में विवेचन करना है।

विवाह संस्था — विवाह का अर्थ एवं परिभाषा :-
 विवाह एक सार्वत्रिक स्वभाव की सामाजिक संस्था है। सभी समाजों में पाई जाती है। लैंगिक वृत्ति मानव की जैविक आवश्यकता है। प्रत्येक समाज अपने सदस्यों के लैंगिक व्यवहार (आचरण) पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। लैंगिक संबंध हेतु सदस्यों का चयन करने की संपूर्ण स्वतंत्रता सदस्यों को प्रदान नहीं की जाती है। प्रत्येक समाज अपने सदस्यों के लैंगिक संबंधों का नियंत्रण स्वयं निम्न करने के लिए कुछ सामाजिक नियम निश्चित करता है। इन सामाजिक नियमों के स्फुट्यम (इव) को विवाह कहते हैं। तथापि केवल लैंगिक वृत्ति अथवा लैंगिक समाधान प्राप्त करना यह विवाह का एकमात्र उद्देश्य या लक्ष्य नहीं है। संतानोत्पत्ति स्वयं बालकों का पालन-पोषण



परिवार की स्थापना, प्रेम संपादन, स्त्री-पुरुष के मध्य सामाजिक एवं आर्थिक सहयोग और भी विवाह के उद्देश्य हैं। विवाह का अर्थ जानने के लिए समाजशास्त्रीयों द्वारा दी गई कुछ परिभाषाओं पर विचार किया जा सकता है।

विवाह की परिभाषाएँ

क) " विवाह समाज की सम्मति प्राप्त लैंगिक सहयोगियों के मध्य सापेक्षतया स्थायी स्वरूप का बंधन है। "

ख) " विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होनेवाला गौण संबंध है, जिसे प्रथा से या कानूनन स्वीकृती होती है, तथा जिसमें दोनों पक्षों के प्रति तथा उसमें जन्म लेने-वाले संतान के प्रति निश्चित अधिकारों तथा कर्तव्यों का समावेश होता है। "

ग) " विवाह स्त्री और पुरुष दोनों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करानेवाली संस्था है। "

घ) " विवाह एक प्रजननमूलक परिवार की स्थापना का समाज स्वीकृत तरीका है। "

च) " विवाह मध्य प्रजननसंपन्न संतान के पालन-पोषण के लिए किसेजानेवाला समझौता है। "



विवाह की विशेषताएँ *

- 1) सामाजिक संस्था —> विवाह समाज की स्मृति प्राप्त एक सामाजिक संस्था है। क्योंकि विवाह भिन्नलिंगीय व्यक्तियों के मध्य अर्थात् पति-पत्नी के मध्य लैंगिक तथा आर्थिक सामाजिक संबंधों को निर्धारित करनेवाले सामाजिक नियमों का समूह है।
- 2) संचालक स्वरूप —> परंपरागत दृष्टिकोण से विवाह दो या अधिक भिन्नलिंगीय व्यक्तियों का संघ है। संघ में कर्तव्य, अनुशासन होता है।
- 3) सामाजिक स्वीकृति —> विवाह को समाज की मान्यता या स्वीकृति की आवश्यकता होती है। समाज की मान्यता न हो तो उसे विवाह नहीं माना जाता या समाज की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही भिन्नलिंगीय व्यक्तियों का संघ वैवाहिक बंधन बनता है। धार्मिक विधि अथवा सामाजिक कानून द्वारा विवाह को सामाजिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 4) स्थायी संबंध —> सामान्यतः विश्व के सभी समाजों में विवाह को पति-पत्नी के बीच एक स्थायी बंधन माना जाता है। पारंपरिक हिन्दु विवाह के अनुसार विवाह एक संस्कार माना जाता है, और इसके कारण वह एक अटूट एवं पवित्र बंधन होता है।
- 5) नियम एवं कानून —> जैसे विवाह में पति-पत्नी के एक-दूसरे के प्रति अधिकार, कर्तव्य एवं विशेषाधिकार आदि का समावेश होता है।



जाति संस्था (Caste Institution) का उदय

भारतीय समाज की संरचना में विवाह और परिवार संस्था की तरह जाती संस्था भी एक महत्वपूर्ण संस्था है।

भारतीय समाज के सभी अंगों एवं व्यवहारों पर जाती प्रथा का गहरा प्रभाव पाया जाता है। इसके कारण भारतीय समाज का अध्ययन करते समय जाती संस्था का अध्ययन करना आवश्यक है।

भारत में प्राचीन काल में हिन्दू समाज का ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य, शूद्र इन चार वर्गों में विभाजन हुआ था। प्रत्येक वर्ग का व्यवसाय, सामाजिक स्तर (दर्जा) और जीवनशैली आदि बातें कस्त्रिय नियमों के द्वारा निर्धारित की गई हैं और इसी के परिणामस्वरूप भारत में वर्णव्यवस्था का उदय हुआ। प्रांमिक समय में व्यक्ति का वर्ण उसके गुणकर्मों के अनुसार निर्धारित होता था। लेकिन आगे चलकर व्यक्ति का वर्ण उसके जन्म से निर्धारित होने लगा। अर्थात् व्यक्ति का वर्ण उसके अभिभावक (माता-पिता) के वर्ण से निश्चित होने लगा और व्यक्ति को वर्ण में परिवर्तन करने से प्रतिबंधित किया गया। इसके पश्चात जनसंख्या वृद्धि के साथ लोगों की तथा समाज की आवश्यकताओं में भी वृद्धि हुई। परिणामः अनेक नए व्यवसाय कार्यों का उदय हुआ। इस कारण प्रत्येक वर्णतंत्रित अनेक समूहों एवं उपसमूहों का निर्माण हुआ। इन्हीं समूहों एवं उपसमूहों को ही जाती-उपजाती के नाम प्रदान किए गये। इस प्रकार वर्णव्यवस्था से विभिन्न जातियों और उपजातियों का उदय हुआ।

विभिन्न जातियों के मध्य एवं उपजातियों के मध्य पारस्परिक संबंध तथा प्रत्येक जाती की जीवनशैली नियमित निश्चित करने के लिए अनेक सामाजिक नियमन (प्रतिमान) बनाए गये। इस प्रकार जाति संस्था का उदय हुआ। वर्तमान समय में भी इस जाती संस्था या जाति प्रथा का भारतीय समाज पर अन्तर्मायिक प्रभाव पड़ा है, और आज भी अधिकांशतः चलाया जाता है।



जाती व अर्थ:

जाती इस हिंदी शब्द के लिये अंग्रेजी भाषा में "caste" इस संज्ञा (शब्द) का प्रयोग किया जाता है।

"कास्ट" यह संज्ञा स्पैनिश शब्द "Casta" अर्थात् "वंश" (ब्रीड अथवा रैत) से बनी है। हिन्दु समाज के विभाजन को संबोधित करने हेतु पुर्तगालियों ने "कास्ट" संज्ञा का प्रयोग किया तथापि "कास्ट" अर्थात् "जाती" यह संज्ञा वंशशुद्धता के कल्पना पर आधारित नहीं है। अनेक विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है, कि "जाती" यह वंश शुद्धता का पैमाना या निदर्शक नहीं है। "जाती" यह अत्यंत संकीर्ण संस्था है तथा उसके अनेक पहलू हैं। केवल "जाती" संज्ञा का प्रयोग करके हमें इन सभी विभिन्न पहलुओं का आकलन नहीं हो सकता हमें इसका अर्थ जानने के लिये इसकी परिभाषा को भी देखना चाहिए।

जाती की परिभाषा:

- 1) "जब कोई वर्ग पूर्णतः अनुवंशिक पर आधारित होता है, तब उसे हम जाती कह सकते हैं।"
- 2) "जाति यह एक अंतर्विवाह समूह है, अथवा अंतर्विवाही समूहों का संकलन है, जिसे एक सामान्य नाम होता है जिसकी सदस्यता अनुवंशिक होती है, जो अपने सदस्यों के सामाजिक संपर्क पर कुछ बंधन डालता है, एक सामान्य परंपरागत व्यवसाय को अपनाता है।"
- 3) जाति एक सामाजिक समूह है, तथा उसकी कुछ विशेषताएँ हैं
 - (अ) विशेष जाति के सदस्य के कौशल से जन्म लिये व्यक्तियों को ही उस जाति की सदस्यता प्राप्त होती है।
 - (ब) अपने सदस्यों को अपने जाति के बाहर के व्यक्ति से विवाह न करने का कड़ा बंधन होता है।



जाति की विशेषताएँ :

जाति के संबंध में उपरोक्त कोई भी परिभाषा-परिपूर्णा एवं संतोषजनक नहीं है और जाति का स्वरूप उसमें व्यक्त नहीं है। कौकी जाती की प्रत्येक परिभाषा में कुछ न कुछ दोष है। प्रत्येक परिभाषा अपने-आप में आधुनी तथा ऊपरी-ऊपरी जाती है। सभी परिभाषाओं में कुछ तत्व समान हैं, और वह हैं, जाति की सदस्यता जन्म पर निर्भर करती है, जाति अपरिवर्तनीय है। डॉ. आबेडेकर तथा डॉ. केटरकर की परिभाषा में कहा गया है, कि जाति एक अंतर्विवाही समूह है। जाति की अन्य विशेषताओं का उल्लेख उपरोक्त परिभाषाओं में नहीं है। जैसे कि पवित्र-अपवित्रता की भ्रमण श्रान-पान या भोजन संबंधी निषेध-निग्रह, सामाजिक प्राप्ति आदी। जाति सदस्य अपने एक ही पूर्वज का स्वीकार नहीं करते।

- 1) जन्माधारित समूह
- 2) पदानुक्रम / श्रेणीरचना
- 3) विशेषाधिकार एवं अनौद्योगिकताएँ
- 4) श्रान-पान एवं सामाजिक संपर्क पर निषेध
- 5) व्यवसाय के चयन पर प्रतिबंध
- 6) विवाह पर प्रतिबंध
- 7) धर्मधारित



॥ भारत की प्रमुख सामाजिक समस्याएँ ॥

MTWTFSS

Date: 15/2/22 Page No. —

भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, स्त्रियों की समस्याएँ तथा किसान आत्महत्या की समस्या इन प्रमुख सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना है। इसके लिए प्रथम सामाजिक समस्या की परिभाषा अर्थात् विशेषताओं को संक्षेप में समझना आवश्यक है।

सामाजिक समस्या का अर्थ एवं परिभाषा

- 1) सामाजिक समस्या: कारण, जनसंख्या वृद्धि के परिणाम तथा प्रतिबंधात्मक उपाय
- 2) स्त्रियों की समस्या: —
 - क) स्त्री-पुरुष असमानता
 - ब) नौकरीपेशा स्त्रियों की समस्याएँ
 - स) दहेज की समस्या
 - द) पारिवारिक या घरेलू हिंसाचार
- 3) किसान आत्महत्या: कारण और प्रतिबंधात्मक उपाय ॥

अर्थ → "समस्या से तात्पर्य ऐसे प्रश्न अथवा कठिनाई या बाधा से है, जिसे हल करने के लिए कुशल उपाय-योजना करना आवश्यक होता है।"

इस प्रकार "समस्या" इस संज्ञा का अर्थ निरूपित जा सकता है। अन्य शब्दों में, "सामाजिक समस्या" का अर्थ है सामाजिक प्रश्न या कठिनाई या बाधा से है, जिस पर कुछ उपाय करना आवश्यक है।

परिभाषा → 1) "सामाजिक समस्याओं में उन क्रियाओं का अथवा आचरण का समावेश होता है, जिन्हें समाज के अधिकांश लोगो समाजविधातक या सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन मानते हैं, तथा जिनमें सुधार करना संभव है, और आवश्यक है, मानते हैं।"



2) " सामाजिक समस्या का तात्पर्य ऐसी परिस्थिति से है, जो अधिकांश लोगों को अवांछनीय ढंग से प्रभावित करती है, और जिसके बारे में सामूहिक कार्यवाही द्वारा कुछेक किया जा सकता है।"

3) " किसी समाज के अधिकांश सदस्यों को जब कोई व्यवहार, आचरण या स्थिति अवांछनीय या आपत्तिजनक लगती है, तब उसे सामाजिक समस्या कहा जाता है। इस समस्या से संधर्ष करने हेतु उभरवा उसकी तीव्रता को कम करने हेतु सुधारसत्मक नीतियाँ, कार्यक्रम या सेवा आदि की आवश्यकता है, इसकी अनुभूती उन सदस्यों को होती है।"

* सामाजिक समस्या से तात्पर्य, समाज की ऐसी स्थिति उभरवा आचरण प्रकार से है, कि जो समाज के अधिकांश सदस्यों को उनके नियमनो (प्रमाणको) एवं मूल्यों से असंगत, अनिष्ट, एवं आपत्तिजनक लगता है, और उसमें सुधार करने हेतु सामूहिक कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत होती है।

सामाजिक समस्या की विशेषताएँ

क) सार्वभौमिक / सर्वव्यापकता → सामाजिक समस्याओं का स्वरूप सार्वभौमिक या सर्वव्यापकता होता है। अर्थात् प्राचीन-वर्तमानकालीन परंपरागत-आधुनिक, प्रगत-अप्रगत, छोटे-बड़े आदि सभी प्रकार के समाजों में सामाजिक समस्या पाई जाती है। विश्व में शायद ही ऐसा कोई समाज नही होगा, जहाँ एक भी समस्या नही है।

ख) व्याक्तिगत समस्या से भिन्न → जो समस्या किसी व्यक्ति या परिवार तक ही सीमित होती है, वह व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्या होती है। इसके विपरीत जिस समस्या के समाज के असंख्य लोग प्रभावित होते हैं, वह सामाजिक समस्या मानी जाती है। अतः सामाजिक समस्या व्यक्तिगत, समस्या से भिन्न होती है। उदा: परिवार में कोई एक व्यक्ति बीमार होगा तो वह वैरीजगरी उस व्यक्ति या उसके परिवार की समस्या होगी।



ग) सापेक्षता → सामाजिक समस्याएँ स्थान, समय एवं व्यक्ति सापेक्ष होती हैं। अर्थात् एक स्थान पर (समाज) में एक रक समय में (कालावधि) जो दशा या स्थिती सामाजिक समस्या मानी जाती है। वह दूसरे स्थान पर एक समय में सामाजिक समस्या होगी यह आवश्यक नहीं है।

उदा * भारत एवं चीन में जनसंख्या वृद्धि सामाजिक समस्या मानी जाती है, लेकिन कुछ यूरोपीय राष्ट्रों में इसे सामाजिक समस्या नहीं मानी जाती।

उसी तरह प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय समाज में सती प्रथा, बालविवाह, विधवाविवाह आदि सामाजिक समस्या नहीं मानी जाती थी। लेकिन ब्रिटीश शासनकाल में इसे सामाजिक समस्या माना गया। सामाजिक समस्याएँ व्यक्तिगत भी होती हैं।

घ) असंगतता → सामाजिक समस्या समाज में प्रचलित सामाजिक प्रमाणक एवं मूल्य के प्रति असंगत (परस्परविरोधी) होती है, अथवा उनका उल्लंघन हो रहा है, माना जाता है। लैंग कौनसा आचरण कर सकते हैं, और कौनसा नहीं कर सकते यह बताने वाले नियमों को प्रमाणक कहते हैं। तो दूसरी ओर कौनसा आचरण उचित है और कौनसा अनुचित यह निर्धारित करने वाले मानकों को अस्था कर्तारियों को मूल्य कहते हैं। जब सामाजिक प्रमाणक एवं मूल्यों में असंगत आचरण की प्रवृत्ति में अत्यधिक वृद्धि होती है, तब यह स्थिती सामाजिक समस्या बन जाती है। वृद्ध भ्राता-पिता की देखभाल करना एक सामाजिक नियम या मूल्य है। यदि इस के उल्लंघन में वृद्धि हुई तब "वृद्धों की समस्या" सामाजिक समस्या बन जाती है।

धूस लेना-देना मना है, लेकिन इस सामाजिक नियम के उल्लंघन की सीमा के बाहर वृद्धि लेने पर "भ्रष्टाचार" एक सामाजिक समस्या हो सकती है।



जनसंख्या की समस्या *

जनसंख्या की समस्या ऊँच सभी समस्याओं की जननी मानी जाती है, क्योंकि इस समस्या के कारण ही अन्य समस्याओं का उद्भव हुआ है। शयनिक जनसंख्या वृद्धि की समस्या को मूलभूत समस्या माना जाता है।

जनसंख्या वृद्धि समस्या का स्वरूप *

यहाँ पर हम भारत की जनसंख्या वृद्धि की समस्या को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानने का प्रयास करेंगे। इसके पहले वैश्विक जनसंख्या वृद्धि के विषय में विचार करना आवश्यक है। आज विश्व को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनमें से एक जनसंख्या की समस्या भी है।

जनसंख्या की समस्या दो तरह की है →

- 1) न्यूनतम जनसंख्या की समस्या
- 2) अतिरिक्त जनसंख्या की समस्या

जब किसी देश की जनसंख्या वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों से कम होती है, तब उस देश के सामने न्यूनतम जनसंख्या की समस्या होती है। उत्पादन बड़ी मात्रा में परन्तु उपभोग कम मात्रा में, वस्तुओं की आपूर्ति अधिक परन्तु माँग कम, मजदूरों - श्रमिकों - कारीगरों की माँग ज्यादा परन्तु आपूर्ति कम हो, तब वहाँ न्यूनतम जनसंख्या की समस्या है, ऐसा माना जाता है।

जब किसी देश की जनसंख्या वहाँ के भौगोलिक - प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में कई अधिक होती है, तब वहाँ के जनता को अनेक जीवनावश्यक वस्तुओं के विषय संघर्ष करना पड़ता है, कई अन्य प्राथमिक समस्याओं से झूझना पड़ता है, जैसे की रोटी, कपड़ा और मकान वहाँ अतिरिक्त जनसंख्या की समस्या कहते हैं।



भारत में जनसंख्या वृद्धि *

विश्व की जनसंख्या की तरह भारत की जनसंख्या भी बढ़ रही है। आज भारत की बढ़ी हुई जनसंख्या भारत के लिए ही एक भयावह समस्या बन गई है। भौतिक विकास एवं उचित नियोजन के अभाव में यह समस्या और भी भयावह बन गई है।

जनसंख्या वृद्धि की तुलना में भारत दूसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर चीन है। जनसंख्या की इस भयावह वृद्धि को "जनसंख्या का विस्फोट" कहा गया है। यह वृद्धि भारत के विश्व स्तर के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी है।

भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण *

भारत में जन्मदर यह सापेक्षता उच्च (अधिक) रहने के कारण तथा मृत्युदर कम होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। इसलिए हमें जन्मदर ज़्यादा और मृत्युदर घटने के लिए उत्तरदायी कारकों को जान लेना समस्या के सही आकलन के लिए आवश्यक है।

भारत में उच्च जन्मदर के कारण / कारक

- 1) वैवाहिक कारक
- 2) शैक्षिक कारक
- 3) आर्थिक कारक
- 4) धार्मिक कारक
- 5) भौगोलिक कारक
- 6) मनोरंजनात्मक कारक
- 7) संयुक्त परिवार प्रणाली
- 8) परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता का अभाव



मृत्यु प्रमाण घटने के कारण *

- 1) चिकित्सीय एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि
- 2) प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण
- 3) शिक्षा प्रसार
- 4) जीवन-स्तर में सुधार

जनसंख्या वृद्धि के परिणाम (प्रभाव) *

जनसंख्या वृद्धि के भारतीय समाज पर अनेक दुपरिणाम हुए हैं। उनमें से कुछ दुपरिणाम निम्नलिखित हैं।

- 1) भूमि पर अतिरिक्त भार (दबाव)
- 2) कृषि भूमि पर भार (दबाव)
- 3) लैरोजगारी
- 4) निर्धनता
- 5) खाद्यान्नो का अभाव (समस्या)
- 6) अनुत्पादन उपभोक्ताओं में वृद्धि
- 7) आर्थिक विकास में बाधा
- 8) मुद्रास्फीति
- 9) पर्यावरणीय न्हास
- 10) रश्मिांतरण

जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के लिए किए गये उपाय *

वास्तविक देखा जाय तो भारत में जनसंख्या का विस्फोट हुआ है, और यदि इस पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो आनेवाले वर्षों में सामाजिक आर्थिक दशा अत्यंत गंभीर बन सकती है। इसके देबते हुए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है।



अ) स्वीकृत उपाय * भारत की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है लेकिन स्वतंत्रतापूर्वक काल में ब्रिटिशों ने जनसंख्या वृद्धि की समस्या की पूर्णतः अनदेखी की। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार का ध्यान इस और गया और लगा कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किए बिना देश की प्रगति नहीं हो सकती।

अतः सरकार ने जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए अभूनिष्ठित उपाय किए हैं।

ग) परिवार नियोजन कार्यक्रम *

- 1) परिवार में बच्चों की संख्या नियंत्रित करना।
- 2) अनचाही संतान का जन्म रोकना।
- 3) मुनचाही संतान को जन्म देना।
- 4) दो संतान (बच्चों) के मध्य अंतर पर नियंत्रण रखना।

सरकार ने परिवार नियोजन के दृष्टि से आवश्यक सभी चिकित्सा सुविधाओं संभूत भारत में उपलब्ध करने के लिए परिवार नियोजन केंद्र स्थापित किए हैं। सन 1966 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को

“ **परिवार कल्याण कार्यक्रम** ” नाम दिया गया। इस परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत परिवार का जीवनस्तर उंचा उठाने के लिए चिकित्सीय एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की आपूर्ति की जाती है। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर आधिकाधिक राशि व्यय की जा रही है।

घ) कानूनी प्रावधान * जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने सरकार ने कुछ कानूनी प्रावधान किए हैं, उनका वर्णन इस प्रकार है।

- 1) विवाह आयु - सीमा में वृद्धि
- 2) गर्भपात को कानूनन स्वीकृती
- 3) अनौद्योगिकी का निर्धारण
- 4) प्रोत्साहक / अमिष्टरेक



जनसंख्या नियंत्रण के लिए सुझाए जाने वाले उपाय

- 1) स्त्री- शिक्षा का प्रसार
- 2) स्त्रियों की प्रशिक्षण (दर्जा) उँचा उठाना
- 3) बालकों / युवाओं की शिक्षा पर बल
- 4) सामाजिक सुरक्षा
- 5) मनोरंजन सुविधा
- 6) बाल मृत्युदर कम करना
- 7) तीव्र आर्थिक विकास
- 8) तीव्र नगरीकरण
- 9) विलंब से विवाह करना
- 10) जनजागृती कार्यक्रम
- 11) लक्ष्मी से वंचित रहना

स्त्रियों की समस्याएँ

मिश्रित की मुख्य सामाजिक समस्याओं में स्त्रियों की समस्याएँ भी महत्वपूर्ण हैं। स्त्रियों की मुख्य समस्याएँ निम्नानुसार हैं।

- अ) स्त्री- पुरुष असमानता
- ब) नौकरीपेशा स्त्रियों की समस्याएँ
- स) दहेज की समस्या
- क) पारिवारिक हिंसाचर की समस्या



॥ राष्ट्रीय एकता ॥

M T W T F S

Date: 17/2/22 Page No. —

राष्ट्र के समक्ष जो अनेक सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनैतिक समस्याएँ हैं, उन समस्याओं का निराकरण करना आवश्यक है। हम राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया को समझने के लिए राष्ट्रीय एकता का अर्थ, उसकी आवश्यकता तथा राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आनेवाली बाधाएँ और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने हेतु किए जा सकनेवाले उपाय आदि आदि का अध्ययन करेंगे।

राष्ट्रीय एकता का अर्थ एवं आवश्यकता

॥ राष्ट्रीय एकता को राष्ट्र की अत्मा माना जाता है।

राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया अपने देश का अस्तित्व, विकास और और स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया काफी जटिल है। राष्ट्रीय एकता की संज्ञा में दो शब्द सम्मिलित हैं। पहला शब्द है, "राष्ट्र" और दूसरा शब्द है, "एकता"।

व्यवहार में देश, राज्य और राष्ट्र यह शब्द समान अर्थ में प्रयोग किये जाते हैं। परन्तु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन शब्दों का अर्थ भिन्न-भिन्न है। "देश" यह शब्द विशेष भौगोलिक क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता है। "राज्य" शब्द का अर्थ देश की राजनैतिक व्यवस्था से होता है। "राष्ट्र" शब्द का प्रयोग सर्वसमावेशक एकता की भावना रखनेवाले समूह के लिए किया जाता है।

राष्ट्रीय एकता यह एक प्रक्रिया है। देश के सभी नागरिकों ने सौत्र (प्रदेश) धर्म, वंश, जाति, भाषा, और संस्कृति के विषय की भिन्नता को भुलाकर हम सब एक हैं। कि भावना रखना ही राष्ट्रीय एकता कहलाती है। सभी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक भिन्नता का त्याग कर लोगों को एक सूत्र में बाँधने, पिरीने की प्रक्रिया को ही राष्ट्रीय एकता कहते हैं।



SHREE

राष्ट्रीय एकता की परिभाषा *

राष्ट्रीय एकता यह अमूर्त अवधारणा है, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक एकता की भावना को बढ़ाती है।

(अ) राष्ट्रीय एकता यह सामाजिक - मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है।

(ब) " हम सब एक हैं " की भावना ही राष्ट्रीय एकता है।

(क) लोगों के मन में समान नागरिकत्व की भावना, समझ तथा राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना ही राष्ट्रीय एकता है।

राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता *

राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है, यह जानने में समझने के लिए देश की ऐतिहासिक, भौगोलिक, क्षेत्रीय (प्रादेशिक) सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि का अवलोकन और सिंहावलोकन करना आवश्यक है।

राष्ट्रीय एकता के कारण *

- 1) देश की स्वतंत्रता एवं सम्पन्नता बनाए रखना।
- 2) सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखना।
- 3) संघराज्य शासन पद्धति की रक्षा करना।
- 4) आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना।

विविधता में एकता *

- 1) भौगोलिक विविधता
- 2) वांशिक विविधता
- 3) धार्मिक विविधता
- 4) जागतिक विविधता
- 5) वर्गीय विविधता
- 6) भाषीय विविधता
- 7) सांस्कृतिक विविधता



विविधता में एकता का स्वरूप *

प्रदेश, भाषा, धर्म, जाति आदि के संबंध में भारत में अनेक प्रकार की विभिन्नता है, परंतु इन सभी विभिन्नता के उपरान्त भी एकसंघता पायी जाती है, जिसके कारण राष्ट्र का निर्माण सर्वम पुनर्निर्माण करने में सहायता मिलती है।

भारत में विविधता में एकता का जो स्वरूप दिखाई देता है, वह निम्न मुद्दों या कारकों के कारण है। यही यहाँ के विविधता में एकता का स्वरूप प्रकट करता है।

- 1) भौगोलिक एकता
- 2) वंशिक एकता
- 3) धार्मिक एकता
- 4) जाति-पाती में एकता
- 5) भाषाई एकता
- 6) राजनीतिक एकता
- 6) सांस्कृतिक एकता

राष्ट्रीय एकता के भागों की बाधाएँ *

- 1) सम्प्रदायवाद / साम्प्रदायिकता
- 2) जातिवाद
- 3) प्रादेशिकतावाद / क्षेत्रवाद
- 4) आतंकवाद
- 5) असमानता
- 6) भाषावाद
- 6) दलीय राजनीति और अन्तर्-स्पर्धा
- 7) राजनीतिकता



राष्ट्रीय एकतात्मता को बढ़ाने हेतु किए गए उपाय ★

१) स्वतंत्रता आंदोलन के समय सभी भारतीयों के मन में राष्ट्रीय एकतात्मता की भावना जाग उठी थी। तथापि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय यह भावना विखंडित हो गई तथा भारत का विभाजन होकर भारत और पाकिस्तान इन दो राष्ट्रों का उदय हुआ। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय एकतात्मता को महत्त्व दिया और राष्ट्रीय एकतात्मता को गतिशील बनाने के लिए संविधान में विभिन्न प्रावधान किए हैं। सरकार ने भी उसके लिए कुछ अंतिम प्रावधान किए हैं। वे प्रावधान इस प्रकार हैं।

- १) संवैधानिक प्रावधान
- २) मूलभूत अधिकार
- ३) संघराज्य पद्धति
- ४) भागदंडीक तत्व
- ५) भाषिय-सामंजस्य
- ६) आर्थिक तथा सामाजिक समानता

- २) शैक्षिक उपक्रम * शिक्षा यह राष्ट्रीय एकतात्मता बढ़ाने का प्रभावी साधन है।
 - १) राष्ट्रीय एकतात्मता को पोषक पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए।
 - २) भारत का इतिहास, सभी धर्मों के मौलिक तत्व, प्रसैणीय रश्मि, भारत के महान हासिभों की पहचान आदि बालों पर बल देना चाहिए।
 - ३) धात्रों के मन पर सत्य, अहिंसा, राष्ट्रप्रेम, स्वतंत्रता, समानता, बंधुओं आदि मूल्यों का प्रभाव डालना चाहिए।
 - ४) धात्रों में वैज्ञानिक वृत्ति निर्माण करनी चाहिए।
 - ५) धात्रों के पूर्वग्रह, अंधविश्वास तथा सामाजिक भेदभाव की वृत्ति को समाप्त कर उनमें सामंजस्य निर्माण करना चाहिए।
 - ६) धात्रों के मन में अपने समान सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत के प्रति आभेमान निर्माण किया जाना चाहिए।



राष्ट्रीय स्वकात्मता के लिए अपनाये जानेवाले उपाय →

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय स्वकात्मता का संवर्धन करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार ने समय-समय पर अनेक उपाय किए हैं इसके लिए और भी प्रयास करने की आवश्यकता है।

- 1) राष्ट्रीय भावना का विकास
- 2) प्रभावी शैक्षिक नीति
- 3) पारदर्शी प्रशासन
- 4) भ्रष्टाचार पर निंत्रण
- 5) प्रसार माध्यमों पर उपयोग
- 6) अ) मुद्रित माध्यम ब) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम
- 7) धार्मिक सामंजस्य (सुसंवाद)
- 8) युवाओं के लिए सम्मान मंच/व्यासपीठ
- 9) केन्द्र-राज्य संबंधों में सुधार
- 10) सभी प्रदेशों के लिए विकास कार्यक्रम
- 11) राष्ट्रीय त्यौहार तथा समारोहों का आयोजन

भारत में सामाजिक परिवर्तन

राष्ट्रीय स्वकात्मता का अर्थ उसके मार्गों की व्यापार और उस पर उपाय आदि का अध्ययन किया है। साथ ही विविधता में एकता खोजने का भी अध्ययन किया है। इस अध्याय में हम भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करनेवाले हैं। "सामाजिक परिवर्तन" समाज-शास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। किसी भी समाज का स्वरूप समझने या ज्ञात करने हेतु उसकी रचना तथा उस रचना में होनेवाले परिवर्तनों का अध्ययन करना आवश्यक है। इस अध्याय में हम अध्ययन करनेवाले हैं आधुनिकीकरण, नगरीयकरण, पाश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण और, लोकतंत्रीकरण, अर्थात् जनतंत्रीकरण आदि प्रक्रियाओं द्वारा भारतीय समाज में होनेवाले परिवर्तन का अध्ययन करनेवाले हैं।

सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया ठिक से समझने के लिए हमें इस अवधारणा का अर्थ ज्ञात करने का प्रयास करेंगे।



सामाजशास्त्र में सामाजिक परिवर्तन इस संज्ञा को एक निश्चित अर्थ है। समाज में होनेवाले प्रत्येक परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। मूलतः सामाजिक संरचना में होनेवाले परिवर्तन को लेकर ही "सामाजिक परिवर्तन" इस संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समझने के लिए उल्लेख्य सामाजशास्त्रीयों द्वारा दी गई सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा को देखेंगे।

- 1) "मूलभूत अर्थ से समाज संरचना में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है।"
- 2) "केवल सामाजिक संगठन में व्यतिरिक्त, सामाजिक संरचना तथा कार्य में होनेवाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है।"
- 3) "सामाजिक संरचना और सामाजिक संबंधों में होनेवाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं।"

आधुनिकीकरण { INDUSTRIALIZATION }

आधुनिकीकरण यह एक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण क्रांती के कारण/प्रभाव के कारण इंग्लैंड में इस प्रक्रिया की शुरुवात हुई। 16 वीं और 17 वीं सदी में वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास हुआ। विभिन्न यंत्र तथा तंत्र आस्तित्व में आए। उत्पादन प्रक्रिया में उनका उपयोग किया जाने लगा। परिणाम: विशाल उद्योगों का निर्माण हुआ। इस उत्पादन पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन को आधुनिक क्रांती कहा गया है।

आधुनिकीकरण क्रांती के प्रभाव-स्वरूप प्रारंभ में यूरोपियन देशों में तथा बाद में विश्व के अन्य देशों में बड़े-बड़े उद्योगों का निर्माण हुआ। इस प्रकार विशाल उपयोग-व्यवसाय में बृद्धि तथा विस्तार की इस प्रक्रिया को ही आधुनिकीकरण कहा गया है।



औद्योगिकरण की परिभाषा

- 1) " वस्तु उत्पादन, यातायात और संचार के लिए भाँप/वायु और विद्युत आदि जैसे अजैविक शक्ति साधनों का प्रयोग करना ही औद्योगिकरण कहलाता है। "
- 2) " आधुनिक वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन हेतु अमानवीय तथा अजैविक शक्ति का बड़े पैमाने पर प्रयोग करना सही औद्योगिकरण का मूलभूत अर्थ है। "
- 3) " औद्योगिकरण यह व्यावहारिक विज्ञान के प्रयोग के द्वारा तकनीकी विकास को साकार करनेवाली प्रक्रिया है। विद्युत चालित यंत्रों द्वारा विशाल मात्रा में उत्पादन होना, उत्पादक तथा उपभोक्ता के लिए वस्तुओं का विकसित बाजार केंद्र उपलब्ध होना, प्रभविभाजन द्वारा कार्य का विशीकरण होना तथा इन सभी बातों के लिए नगरीयकरण द्वारा गति मिलना यह इस प्रक्रिया की विशेषताएँ हैं। "

औद्योगिकरण का अर्थ

- 1) वैज्ञानिक ज्ञान पर निर्भर मंत्र तथा तंत्र का प्रयोग करके वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने की प्रक्रिया का तात्पर्य ही औद्योगिकरण है।
- 2) मानवीय अथवा जैविक शक्ति के अतिरिक्त अमानवीय अथवा अजैविक शक्ति पर चलनेवाले मंत्र तथा साधनों का प्रयोग करना ही औद्योगिकरण है।
- 3) उत्पादन पध्दती, फसल बुआई की पध्दती, यातायात तथा संचार पध्दती का यंत्रिकीकरण होना औद्योगिकीकरण है।



औद्योगिकीकरण की विशेषताएँ *

- 1) उत्पादन व्यवस्था का मांत्रिकीकरण
- 2) कारखाना पध्दती
- 3) प्रमविभाजन और विशेषीकरण
- 4) यातायात तथा संचार साधनों का विकास
- 5) पूँजी को प्राथमिकता
- 6) लाभ-प्राप्ति के लिए उत्पादन
- 7) नगरीयकरण को प्रेरना/संवर्धन
- 8) कृषि उत्पादन तकनीकी में परिवर्तन
- 9) सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया

औद्योगिकीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव

हमने औद्योगिकीकरण का अर्थ तथा विशेषताओं का अध्ययन किया है। अब हम औद्योगिकीकरण के कारण भारतीय समाज में घटित हुए सामाजिक परिवर्तनों के स्वरूप का अध्ययन करेंगे।

ब्रिटिश-काल में भारत में औद्योगिकीकरण का प्रारंभ हुआ।

वस्त्र, रसायन, औषधी, खाद, लोहे, आदि विभिन्न क्षेत्रों में बड़े-बड़े उद्योगों का निर्माण हुआ। सन 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। उसके बाद भारत-सरकार ने औद्योगिकीकरण विकास पर विशेष लक्ष्य केंद्रित किया। परिणामतः स्थानीय उद्योगों में तेजी से वृद्धि होने में सहायता मिली है। औद्योगिक नकशों पर भारत को लाने के लिए सरकार ने विशाल मात्रा में पूँजी-निवेश की माँग करनेवाले भारी उद्योगों के क्षेत्र में प्रवेश करना तय किया। संकुचित उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहन तथा सहायता उद्योगों का शीघ्र विकास करने हेतु सरकार ने अनेक भारी उद्योग संघों में स्थापित किए। इस प्रकार औद्योगिकीकरण के प्रभाव के कारण भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन हुआ।



PRINCIPAL
Yashoda Girls Arts & Commerce College
Bich Nagar, Nagpur-15